

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./ट्रोमा/2019/386

दिनांक: 08/05/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय – गुड सेमेरिटन पावती (रिसिप्ट) की प्रतिलिपि सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ – उप परिवहन आयुक्त (स सु), परिवहन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 10(698) परि/स सु/2015/पार्ट-V/6989 दिनांक 29.04.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.05.2015 को जारी अधिसूचना के बिन्दु 13 "यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन चाहे तो अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में, उस गुड सेमेरिटन को एक पावती (रिसिप्ट) उपलब्ध करायेगा तथा ऐसी पावती (रिसिप्ट) को राज्य सरकार द्वारा एक मानक फॉर्म में तैयार किया जायेगा तथा उपयुक्त समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया जायेगा।"

सलग्न गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन पत्र सभी राजकीय एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे ताकि गुड सेमेरिटन द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुँचाये जाने पर मानक पावती (रिसिप्ट) उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./ट्रोमा/2019/386

दिनांक: 08/05/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 4 उप परिवहन आयुक्त (स सु), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in)
- 5 समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
- 6 नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Inpandey434@gmail.com)
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सभी को ईमेल कर साथ ही उक्त अधिसूचना की अनुपालना में मानक पावती (रिसिप्ट) की प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वेब साइट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करावे।
- 8 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

trauma.rajasthan@gmail.com

Page 1 of 7

①

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

27/3/19
Addl (HA)
1-5

HA-269
2/5/19

क्रमांक प. 10(698) परि/स.सु./2015/पार्ट-V/ 6989

दिनांक 29/4/19

निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- गुड सेमेरिटन पावती (Receipt) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर
अपलोड कराने बाबत।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना
के क्रम में।

महोदय,

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), नई दिल्ली द्वारा दिनांक
12.05.2015 को जारी अधिसूचना के बिन्दु 13 "यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन चाहे तो
अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में, उस गुड
सेमेरिटन को एक पावती (Receipt) उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी पावती (Receipt) को राज्य सरकार
द्वारा एक मानक फार्मेट में तैयार किया जाएगा तथा उपयुक्त समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड
सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया
जाएगा।" के अनुसार गुड सेमेरिटन नागरिक द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को
अस्पताल पहुंचाये जाने पर गुड सेमेरिटन को उपलब्ध करवायी जाने वाली मानक पावती
(Receipt) तैयार कर राज्य के सभी अस्पतालों में वितरित करने हेतु लिखा गया है।

अतः निर्देशानुसार उक्त अधिसूचना की अनुपालना में मानक पावती (Receipt) की प्रति
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा
रही है ताकि आवश्यकतानुसार राज्य के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों द्वारा पावती
(Receipt) को डाउनलोड कर गुड सेमेरिटन नागरिक चाहे तो उसे यह पावती (Receipt) उपलब्ध
कराई जा सके।

साथ ही आपके अधीन समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों को निर्देशित करावे
कि वे उनके द्वारा गुड सेमेरिटन को उपलब्ध कराई जाने वाली पावती (Receipt) की सूचना
संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय को त्रैमासिक रूप से भिजवाना
सुनिश्चित करें। कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को 15 दिवस में अवगत
कराने का भी कष्ट करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न: 1. पावती (Receipt)।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना।

(निधि सिंह)

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)

क्रमांक प. 10(698) परि/स.सु./2015/पार्ट-V/ 6990-92

दिनांक 29/4/19

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

नोडल आफिसर (स.सु.)

2

गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति
निवासी मोबाइल नं.
द्वारा दिनांक को बजे सड़क
दुर्घटना में घायल व्यक्ति (नाम) को इस
अस्पताल में लाया गया।

अस्पताल द्वारा इनको सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की
मदद करने पर प्रोत्साहन के रूप में यह पत्र जारी किया जा
रहा है।

जारी करने वाले व्यक्ति
का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

अस्पताल का नाम

पता

दूरभाष

ई-मेल

नोट :-

1. अस्पताल द्वारा यह प्रोत्साहन पत्र गुडसेमेरिटन द्वारा चाहने पर जारी किया जाएगा।
2. अस्पताल द्वारा इस प्रोत्साहन पत्र की प्रतियां सकलित कर त्रैमासिक रूप से सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
 EXTRAORDINARY
 भाग I—खण्ड 1
 PART I—Section 1
 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]
No. 126]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. 25035/101/2014-आरएस.- जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 235 में सेवलाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के संबंध में गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाव के लिए इसे आवश्यक समझती है तथा, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।
- (2) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित इनाम या मुआवजा दिया जाएगा।
- (3) बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (4) कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- (5) गुड सेमेरिटन का नाम और उसके विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैश्विक बनाया जाएगा। ऐसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मैडिको लीगल केस (एमएलसी) फार्म में भी किया जाएगा।
- (6) उन लोक अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जाएगी जो किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य करेंगे अथवा धमकाएंगे।
- (7) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमे के दौरान जांच-पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उत्पीड़ित अथवा धमकाया ना जाए।
- (8) जांच की विधियां, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किसी आयोग द्वारा, अथवा कथित संहिता की धारा 296 के अनुसार औपचारिक तौर से शपथ-पत्र के द्वारा हो सकती है तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी।
- (9) गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए, बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन एवं उपर्युक्त
- (1) दिशा-निर्देश में संदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, से पूछताछ के दौरान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।
- (10) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करेगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पताल बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को न रोके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा-संबंधी न हो तथा पं. परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [1989] 4 एससीसी 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए।
- (11) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में, जिस समय डाक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है, किसी डाक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनियम, 2002 के अध्याय-7 "व्यवसायिक कदाचार" के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा तथा उस डा. के विरुद्ध कथित विनियमन के अध्याय-8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (12) सभी अस्पताल इस आशय का अपने प्रवेश द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को नहीं रोकेंगे अथवा किसी पीड़ित के उपचार के लिए उनसे धन जमा कराने के लिए नहीं कहेंगे।
- (13) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन घाटे को अस्पताल से भुगतान व्य. को अस्पताल में लाते तथा समय और धन के अभाव में गुड सेमेरिटन को घाटे या घाटे करारिया अथवा ऐसी पत्रों को राज्य सरकार द्वारा एक मौखिक कांवेन्शन के तहत उपयोग के लिए समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों के संबंधित कर्मियों को सूचित किया जाएगा।
- (14) सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल रूप से किया जाएगा तथा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा उल्लंघन किए जाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
- (15) इन दिशा-निर्देशों से युक्त एक पत्र केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत सभी अस्पतालों और संस्थानों में जारी किया जाएगा जिसमें इस अधिसूचना की राजपत्रित प्रति भी सलग्न होगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन दिशा निर्देशों के बारे में आम जनता को सूचित किए जाने हेतु सभी राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।
- 2 बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देश, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134 के तहत यथाविनिर्दिष्ट सड़क दुर्घटना में किसी मोटर वाहन के चालक के दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह की धारणा रचिन हैं।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2015

No. 25035/101/2014-RS.—Whereas the Hon'ble Supreme Court in the case of Savelif Foundation and another V/s. Union Of India and another in Writ Petition (Civil) No. 235 of 2012 *vide* its order dated 29th October, 2014, inter alia, directed the Central Government to issue necessary directions with regard to the protection of Good Samaritans until appropriate legislation is made by the Union Legislature;

And whereas, the Central Government considers it necessary to protect the Good Samaritans from harassment on the actions being taken by them to save the life of the road accident victims and, therefore, the Central Government hereby issues the following guidelines to be followed by hospitals, police and all other authorities for the protection of Good Samaritans, namely:-

1. (1) A bystander or good Samaritan including an eyewitness of a road accident may take an injured person to the nearest hospital, and the bystander or good Samaritan should be allowed to leave immediately except after furnishing address by the eyewitness only and no question shall be asked to such bystander or good Samaritan.
- (2) The bystander or good Samaritan shall be suitably rewarded or compensated to encourage other citizens to come forward to help the road accident victims by the authorities in the manner as may be specified by the State Governments.
- (3) The bystander or good Samaritan shall not be liable for any civil and criminal liability.
- (4) A bystander or good Samaritan, who makes a phone call to inform the police or emergency services for the person lying injured on the road, shall not be compelled to reveal his name and personal details on the phone or in person.
- (5) The disclosure of personal information, such as name and contact details of the good Samaritan shall be made voluntary and optional including in the Medico Legal Case (MLC) Form provided by hospitals.
- (6) The disciplinary or departmental action shall be initiated by the Government concerned against public officials who coerce or intimidate a bystander or good Samaritan for revealing his name or personal details.
- (7) In case a bystander or good Samaritan, who has voluntarily stated that he is also an eye-witness to the accident and is required to be examined for the purposes of investigation by the police or during the trial, such bystander or good Samaritan shall be examined on a single occasion and the State Government shall develop standard operating procedures to ensure that bystander or good Samaritan is not harassed or intimidated.
- (8) The methods of examination may either be by way of a commission under section 284, of the Code of Criminal Procedure 1973 or formally on affidavit as per section 296, of the said Code and Standard Operating Procedures shall be developed within a period of thirty days from the date when this notification is issued.
- (9) Video conferencing may be used extensively during examination of bystander or good Samaritan including the persons referred to in guideline (1) above, who are eye witnesses in order to prevent harassment and inconvenience to good Samaritans.
- (10) The Ministry of Health and Family Welfare shall issue guidelines stating that all registered public and private hospitals are not to detain bystander or good Samaritan or demand payment for registration and admission costs, unless the good Samaritan is a family member or relative of the injured and the injured is to be treated immediately in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court in Pt. Parmanand Katara vs Union of India & Ors [1989] 4 SCC 286.
- (11) Lack of response by a doctor in an emergency situation pertaining to road accidents, where he is expected to provide care, shall constitute "Professional Misconduct", under Chapter 7 of the Indian Medical Council (Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2002 and disciplinary action shall be taken under section 8 of the said Regulations.
- (12) All hospitals shall publish a charter in Hindi, English and the vernacular language of the State concerned.

territory at their entrance to the effect that they shall not detain bystander or good Samaritan or ask depositing money from them for the treatment of a victim.

(13) ~~In case a bystander or good Samaritan so desires, the hospital shall provide an acknowledgement to such good Samaritan, confirming that an injured person was brought to the hospital and the time and place of such occurrence and the acknowledgement may be prepared in a standard format by the State Government and disseminated to all hospitals in the State for incentivising the bystander or good Samaritan as deemed fit by the State Government.~~

(14) All public and private hospitals shall implement these guidelines immediately and in case of noncompliance or violation of these guidelines appropriate action shall be taken by the concerned authorities.

(15) A letter containing these guidelines shall be issued by the Central Government and the State Government to all Hospitals and Institutes under their respective jurisdiction, enclosing a Gazette copy of this notification and ensure compliance and the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Road Transport and Highways shall publish advertisements in all national and one regional newspaper including electronic media informing the general public of these guidelines.

2. The above guidelines in relation to protection of bystander or good Samaritan are without prejudice to the liability of the driver of a motor vehicle in the road accident, as specified under section 134 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt Secy